





# नहीं टाले जाएंगे यूपी चुनाव, आयोग ने कहा- सभी दल चाहते हैं समय पर ही हो यूपी विधानसभा चुनाव

लखनऊ, 30 दिसम्बर (एजेसी)। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा ने गुरुवार को कहा कि लखनऊ दौरे के दौरान उनसे मिलने वाले सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने विधानसभा चुनाव सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर कराए जाने की मांग की है।

यह इस बात का संकेत है कि चुनावी राज्यों में चुनाव स्थगित नहीं होंगे।

अपने तीन दिवसीय दौरे के अंत में मीडिया को संबोधित करते हुए, सीईसी सुशील चंद्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब 52.08 लाख नए मतदाता हैं जो आगामी विधानसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए 11,000 और मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा, 'हमें अधिकारियों के पश्चाती होने की कुछ शिकायतें मिलीं और हमने सभी शिकायतों और सुझावों को नोट कर लिया है।' उन्होंने आगे कहा कि जागरूकता अभियानों के परिणामस्वरूप लगभग 28.86 लाख नई महिला मतदाताओं का नामोंकन हुआ है, जो पुरुषों की तुलना में पांच लाख अधिक है।

उन्होंने कहा, 'महिला

मतदाताओं का लिंगानुपात भी 2017

में 839 से बढ़कर 2021 में 868

दिल्ली में ओमिक्रॉन का कम्प्युनिटी स्प्रेड शुरू : सत्येंद्र जैन



राजेश अलख

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज गुरुवार को चेतावनी देते हुए कहा कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के लिए निवारक उपायों के बारे में बात करते हुए, मंत्री जैन ने कहा कि दिल्ली ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पहल की है। शहर में ग्रेडेड रिस्पास एक्शन प्लान (जीआरएपी) के पहले चरण को लागू किया गया है।

उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज जिम, स्पा बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो और बसों में बैठने की क्षमता को घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। मंत्री ने कहा, 'हमने बड़े पैमाने प्रतिबंध लगाए हैं।'

जैन ने कहा, 'हमें एक स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए अगले दो से तीन दिनों तक इंतजार करना होगा।'

उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिबंध का परिणाम छह से सात दिनों के बाद दिखाई देता है।

अस्पतालों में 200 मरीजों में से 115 एयरपोर्ट से लाए गए। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक

यूपी को परिवारवाद .....  
डबल इंजन की सरकार में आज देश व प्रदेश का माहात्म कैसा है, ये भी सबके सामने है। सरकारों ने अपने स्वार्थ और परिवारवाद की राजनीति के चक्ररथ में देश और प्रदेश को लूट, खरोंट, भ्रष्टाचार और अराजकता का अड्डा बना दिया था। तोहार आते ही प्रदेश में दंगे शुरू हो जाते थे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता ने भरोसा जताया तो आज देश में न आतंकवाद का नामोनिशान रह गया और ना यूपी में दंगा फसाद हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा ने न सिफ्क गांव के गरीब किसानों, मजदूरों के हित में काम किया बल्कि करोड़ों लोगों की आप्या का सम्मान भी किया। अयोध्या में बन रहा भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर इस बात का प्रमाण है कि शासन-प्रशासन यदि अपना काम सही ढंग से करेगा तो विकास भी होगा और अपन चैन भी आयेगा।

केंद्रों पर भीड़ को रोकने के लिए हो गया है।

सीईसी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी और उन्हें पोस्टल बैलेट का विकल्प भी दिया जाएगा, जिसकी सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी।

'हमने संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने और

मतदाताओं के लिए पानी, शौचालय,

बैठने की व्यवस्था, रैप और व्हील चेयर की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी

उन्होंने कहा कि चुनाव छड़वी पर तैनात सभी कर्मियों का पूर्ण टीकाकरण किया जाएगा, जबकि मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनर, पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-

व्यवस्था की विस्तृति के बारे में चर्चा

अधिकारियों से बात की है और उन्हें टीकाकरण को तेज करने के लिए कहा है ताकि चुनाव के समय तक योग्य आवादी का टीकाकरण

की ओर उनसे मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मतदान केंद्रों पर

अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मी तैनात हो सके।

चुनाव आयोग इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में 10 मॉडल बृथ भी बनाएगा। चंद्रा ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-

व्यवस्था की विवरण न हो।



## GOVERNMENT OF SIKKIM SOCIAL WELFARE DEPARTMENT 5TH MILE TADONG, GANGTOK

Memo No: GOS/562/SWD/EC/2021-22/10

### NOTICE INVITING TENDER (RE-TENDER)

The Divisional Engineer, (SW) Social Justice & Welfare Department, Government of Sikkim, Samaj Kalyan Bhawan, Lumsey, Tadong, East District, Sikkim on behalf of Governor of Sikkim, Invites sealed tenders in percentage Rate basis from the eligible contractors of appropriate class Vide Notification No. 584/R&B/PWD/Secy. Dated 08.10.2018 Vide Notification No. 515/R&B/PWD/Secy, Dated:12.06.2018 Notification No. 104/R&B Dated 08.10.2020 for the work(s) listed under:-

#### 1. Construction of CSC Mandap at Bikmat Ward no.6, Namchi, South Sikkim

SL.No	Name of work	Value put to Tender (in Rs.)	Completion Time, (in months)	Amount of Earnest Money @ 2.5% For issue of tender form (Rs.)	Amount of Bank receipt for cost of tender documents(Rs.)	Constituency / GPU/ Ward
1	2	3	4	5	6	7
1.	Construction of CSC Mandap at Bikmat Ward no.6, Namchi, South Sikkim.	1,34,75,878.00	18 months	3,36,897.00	30,000.00	Namchi/ Bikmat/Ward No. 6.

Time Schedule is as follows:-

- 1. Date for submission of applications -10<sup>th</sup> January to 31<sup>st</sup> January, 2022 (10 a.m. to 4:30 p.m.)
- 2. Last date for issue of tender form -07<sup>th</sup> February, 2022 (10 a.m. to 4:30 p.m.).
- 3. Date and Time for submission of Tender -09<sup>th</sup> February, 2022 (10 a.m. to 1:00 p.m.).
- 4. Date and Time of opening of Tender -09<sup>th</sup> February, 2022 at 2:00 p.m. in the respective ward.

Note: The details of tender documents including tender form can be obtain from the office of the Divisional Engineer (South/West), SJWD on production of receipt of deposit made to the respective Ward.

- Tender is open only to the eligible Contractors/Firms of appropriate Class/Area.
- The intending tenders/contractors should apply in writing for issue of tender documents. The application would invariably be signed by the contractor himself/herself. The tender documents will not be issued to any person other than the INTENDING TENDER.

- The applicants should enclose attested copies of the (a) Valid GSTIN Registration Certificate, (b) Latest Income Tax Clearance Certificate as per the Indian Income Tax Act and (c) Validated Contractor Enlistment Certificate, and Professional Tax Clearance Certificates along with the application. It is mandatory to produce the original validated/updated Enlistment Certificate during sale/issue of the Tender Document for verification (d) PAN card. The selected bidder will have to produce valid GSTIN registration certificate before issue of work order.

- The prescribed Non-Transferable Tender Documents (excluding the Tender Form) can be obtained during the period specified as above from the office of the Assistant Engineer (South) of Social Justice & Welfare Department, Samaj Kalyan Bhawan, Lumsey, Tadong, East District, Sikkim, on production of receipt deposit to the revenue of the respective GPU for cost of tender documents.
- Earnest Money Deposit @2.5 % in the state bank of Sikkim in the form of deposit receipt of schedules bank which includes in the form of temporary deposit receipts fixed deposits receipts in favor of the Additional Chief Engineer, Social Welfare Department, Samaj Kalyan Bhawan, Lumsey, Tadong, East District, Sikkim. Tender Form shall be issued only on the production of the deposit receipt to the contractors who has obtained the tender documents, on production of deposit receipts of 2.5% earnest money.

- The Tender documents, including the Tender Form with quoted offer should be placed in a sealed cover with the name of the Tenderers and the name of the work superscribed on it. Supporting documents listed at SL3 (a), (b) and (c) above should be enclosed with the offer.
- Sealed Tenders may be deposited in the Tender Box in the concerned ward on the date and time indicated above.
- Tenders will be opened by a Tender Opening Committee as prescribed by the Government in the presence of the tenderer on the date and time indicated above.

- The Tendered should sign on every page of the tender documents as Acceptance of the General Direction and Conditions of Contract and other laid down norms. The rate quoted should be both in figures and words and should be inclusive of GST and all other Taxes and Levies. Over writing and correction should be avoided and if made should be authenticated. Incomplete/ Conditional tenders shall be rejected forthwith.

- In case of any discrepancy in rate(s) printed in the Schedule of Rates and Quantities issued with the tender document, rates as per approved Schedule of Rates will be taken as correct. For items outside the SOR, the rates shall as per the technically checked/estimate/analysis. Decision of the Chief Engineer/Add. Chief Engineer/Secretary/Head of the Department will be final in this regard.

- The Work Value, scope and quantum of work are subject to change, the contractor shall execute the work as per the directives of the Department. No claim on this account shall be entertained whatsoever. If any extra claim is made, it shall be as per the agreement rates.

- Avoidable damages due to negligence of the contractor shall be at his own risk and cost. The Department shall not be liable for payment of such damages (if any), including accidents to laborer at site.

- The offer shall remain valid for a period of 90 days. The work should commence within 15 days from the date of issue of work order.

- The department reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason thereof.

- Subletting of contract work is against the norms and if it comes to the notice, the original contract shall be cancelled and appropriate action shall be initiated as per the rules.

- The Department also reserves the right to increase, decrease, alter or modify the item of works as indicated in the NIT without assigning any reason thereof.

- The contractor will have to pay all taxes and duties as applicable and notified by the State/Central Government and no claim shall be entertained in this regard whatsoever.

- The rate quoted shall be inclusive of prevailing taxes.

- The department reserves the right to reject the incomplete tender without any reasons there-off.

- The Contractor has to submit the work program / bar Chart in the initial stage.

Note: It is requested to forward the bill in the office of the undersigned for settlement of payments, please.

Sd/-  
Divisional Engineer (South/West),

Social Welfare Department,

5th Mile, Lumsey,

R.O. No.:298/PR/PUB/Class/21-22  
Date: 29.1

## पेट्रोल पर रियायत

झारखंड सरकार अगर दोपहिया चालकों को 25 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की रियायत देने जा रही है, तो यह फैसला न केवल ऐतिहासिक, बल्कि दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय भी है। इस वर्ष पेट्रोल, डीजल के भाव में जिस तरह बढ़ोतार हो रही थी, उसकी जरूरत सरकारों को भले हो, लेकिन इसकी निरा भी खूब हो रही है। केंद्र सरकार और ज्यादातर राज्यों ने नंबर बोर्ड की शुरुआत के बाद से ही वैट या उत्पाद शुल्क में कमी करके ग्राहकों को राहत देने की कोशिश की है। मई से लगातार हो रही वृद्धि के बाद एक समय तो ऐसा भी आया था, जब प्रति लीटर पेट्रोल पर महज उत्पाद शुल्क ही 40 रुपये के करीब और डीजल पर 30 रुपये के करीब पहुंचने लगा था। एक समय ऐसा लगने लगा था कि पेट्रोल की कीमत अब सौ रुपये से नीचे नहीं आएगी, लेकिन नवंबर में लोगों को राहत देने की कोशिश शुरू हुई। अब यदि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की होड़ शुरू हो जाए, तो आश्चर्य नहीं। अक्सर चर्चा होती रहती है कि गरीबों व जरूरतमंदों को ज्यादा राहत मिलनी चाहिए, पर इस दिशा में झारखंड सरकार की ताजा कोशिश एक मिसाल है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए एलान के बाद राज्य में मोटरसाइकिल और स्कूटर चालकों में खुशी की लहर है, और दूसरे राज्यों में भी लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पेट्रोल की कीमत अगर एकमुश्त 25 रुपये प्रति लीटर कम होती है, तो झारखंड में पेट्रोल की कीमत करीब 74 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। लगभग साढ़े तीन साल पहले देश में पेट्रोल की कीमत यही थी। झारखंड में अभी पेट्रोल की कीमत दूसरे राज्यों से तुलनात्मक रूप से ज्यादा ही है। अतः स्वाभाविक ही राज्य सरकार पर कुछ दबाव भी होगा। वैसे झारखंड में दोपहिया चालकों को 26 जनवरी से यह लाभ मिलना शुरू होगा। हेमंत सोरेन की सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर यह राज्य के नागरिकों को एक तोहफा ही है, लेकिन इसे जन-जन तक पहुंचाने का काम आसान नहीं होगा। क्या यह रियायत देने के लिए हर पेट्रोल पंप पर दोपहिया वाहनों के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी? बढ़े पेट्रोल पंप पर इसे लागू करना आसान होगा, लेकिन दूरदराज के इलाकों में छोटे पेट्रोल पंपों पर इसे लागू करने में मुश्किल आ सकती है। इसके अलावा क्या यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इस रियायत का दुरुपयोग नहीं होगा? अगर इसी कीमत पर चौपहिया वाहनों में भी पिछले दरवाजे से पेट्रोल भरने लगे, तो लगाम कैसे लगेगी? पेट्रोल पंपों की ईमानदारी वैसे भी संदेहास्पद ही रही है, तो रियायत की नई व्यवस्था से पारदर्शिता और प्रभावित होगी। गरीबों या जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की कोई भी कोशिश स्वागतयोग्य है, लेकिन उनके लिए दी जा रही रियायत के रिसाव को कैसे रोका जाएगा? दिलचस्प यह है कि अब बाकी राज्य भी झारखंड की नई रियायत व्यवस्था के क्रियान्वयन को देखना चाहेंगे। इस अपेक्षाकृत नए राज्य के पास एक मौका है कि इस रियायत का यथोचित व्यावहारिक ढांचा विकसित हो, ताकि ईंधन के भाव बढ़ने पर कम आय वाले लोगों पर असर न पड़े। हम यह देख पा रहे हैं कि पेट्रोल के भाव बढ़ने से देश भर में सड़कों पर साइकिलों की संख्या बढ़ रही है। अतः इस देश में ईंधन संबंधी किसी भी रियायत या सब्सिडी को सही हाथों तक पहुंचाने की व्यवस्था चाक-चौबंद होनी चाहिए।

## राजनारायण जैसे लोग अब सियासत में क्यों नहीं?



गोपाल जी राय

सुप्रियस नामक चालक नेता राममनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि 'जब तक राजनारायण जैसे ताजा राय नहीं आसंभव है, देश में ताजारायी का आसार भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। अखिर है! इसलिए आज मैं यह सवाल उठा रहा हूँ कि राजनारायण जैसे तुर्दिन की परिकल्पना राममनोहर लोहिया और राजनारायण ने की थी। क्या समाजवादी राजनीति में उनके जैसे लोगों का अकाल पड़ गया है?

आज के दौर में यह सवाल इसलिए अहम है कि समाजवादी सियासत करने वाले क्षेत्रीय दल प्रधानमंत्री नंदें भोजी पर ताजारायी का आरोप लाता रही थी। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की भी यही तोहमत है। यही बजह है कि मुझे अनायास राम मनोहर लोहिया की उपरोक्त टिप्पणी यदि आई, जो उहाँने राजनारायण सिंह को लेकर एक खास सियासी मौके पर कही थी।

सवाल है कि आखिर राजनारायण कौन हैं और भारतीय सियासत में उनकी रिकॉर्ड क्यों

महसूस की जा रही है, इसी बात की चर्चा में आगे कहाँगा, ताकि भारतीय राजनीति के इस हरफनमीला योद्धा की खातिर को अधिकतम तक कोई समझौता नहीं किये। उनका निधन 31 दिसम्बर 1986 को हुआ था। इसी दिन राजनारायण की लोकप्रियता का एहसास देश-दुनिया को हुआ था, जबकि उनके गुजरे हुए 11 साल हो चुके थे।

कहना न होगा कि ऐसी विवादास्पद घटना के बीच 8 सितंबर 1958 को ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पड़ चुके थे, जब कांग्रेस सरकार द्वारा गिरफतार अपने

987 कार्यकर्ताओं का मामला

राजनारायण ने अपने साथी 12 विधायकों समेत उठाया था। लेकिन तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री संपूर्णनंद ने इस मसले पर सदन में चर्चा का विरोध किया, जिससे मामला बढ़ता गया। लेकिन राजनारायण की अपनी मांग पर अंत अंत तक अड़े रहे।

इसके बाद सत्ता के मद में चूर मुख्यमंत्री संपूर्णनंद ने राजनारायण को विधानसभा से पंदर हिंदू दिवस के लिए उत्तरायण के उद्धारित किया। उत्तरायण को वर्ष 1950, 1960, 1970 और 1980 के दशक की सियासी परिस्थितियों और उससे अर्जित समाजवादी उपलब्धियों की ओर ज़माना होगा, जहां उनके कांग्रेसी विधायकों को हुआ था। इसी दिन राजनारायण की लोकप्रियता का एहसास देश-दुनिया को हुआ था, जबकि उनके गुजरे हुए 11 साल हो चुके थे।

कहना न होगा कि वह राजनारायण ही थे, जिन्होंने खुद को राजनारायण राज्य पर मुख्यमंत्री ईदिरा गांधी को न्यायालय और मरदाना (टोटा) दोनों में शिक्षक दी थी। उत्तरायण के लिए उत्तरायण को वर्ष 1950, 1960, 1970 और 1980 के दशक की सियासी परिस्थितियों और उससे अर्जित समाजवादी उपलब्धियों की ओर ज़माना होगा, जहां उनके गुरु नव्यवाची विषयों में उत्तरायण-पतन की समस्त गाथाएं अंतर्निहित हैं।

कहना न होगा कि वह राजनारायण ही थे, जिन्होंने खुद को राजनारायण राज्य पर मुख्यमंत्री संपूर्णनंद ने राजनारायण को विधानसभा से पंदर हिंदू दिवस के लिए उत्तरायण को वर्ष 1950, 1960, 1970 और 1980 के दशक की सियासी परिस्थितियों और उससे अर्जित समाजवादी उपलब्धियों की ओर ज़माना होगा, जहां उनके गुरु नव्यवाची विषयों में उत्तरायण-पतन की समस्त गाथाएं अंतर्निहित हैं।

इसलिए सियासी हल्के में आज यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस नेत्री ईदिरा गांधी को समाजवादी नंदें भोजी पर हर ऐरे इंदिरागांधी पर भी उसी तरह से आज भारतीय प्रधानमंत्री नंदें भोजी पर हर ऐरे इंदिरागांधी पर हो जाएगा। उत्तरायण के लिए उत्तरायण को वर्ष 1950, 1960, 1970 और 1980 के दशक की सियासी परिस्थितियों और उससे अर्जित समाजवादी उपलब्धियों की ओर ज़माना होगा, जहां उनके गुरु नव्यवाची विषयों में उत्तरायण-पतन की समस्त गाथाएं अंतर्निहित हैं।

राजनारायण को समझने के लिए क्या है? जिसके लिए उत्तरायण को वर्ष 1950, 1960, 1970 और 1980 के दशक की सियासी परिस्थितियों और उससे अर्जित समाजवादी उपलब्धियों की ओर ज़माना होगा, जहां उनके गुरु नव्यवाची विषयों में उत्तरायण-पतन की समस्त गाथाएं अंतर्निहित हैं।

राजनारायण को समझने के लिए क्या है?

जिसके लिए उत्तरायण को वर्ष 1950, 1960, 1970 और 1980 के दशक की सियासी परिस्थितियों और उससे अर्जित समाजवादी उपलब्धियों की ओर ज़माना होगा, जहां उनके गुरु नव्यवाची विषयों में उत्तरायण-पतन की समस्त गाथाएं अंतर्निहित हैं।

जिसके लिए उत्तरायण को वर्ष 1950, 1960, 1970 और 1980 के दशक की सियासी परिस्थितियों और उससे अर्जित समाजवादी उपलब्धियों की ओर ज़माना होगा, जहां उनके गुरु नव्यवाची विषयों में उत्तरायण-पतन की समस्त गाथाएं अंतर्निहित हैं।

जिसके लिए उत्तरायण को वर्ष 1950, 1960, 1970 और 1980 के दशक की सियासी परिस्थितियों और उससे अर्जित समाजवादी उपलब्धियों की ओर ज़माना होगा, जहां उनके गुरु नव्यवाची विषयों में उत्तरायण-पतन की समस्त गाथाएं अंतर्निहित हैं।

जिसके लिए उत्तरायण को वर्ष 1950, 1960, 1970 और 1980 के दशक की सियासी परिस्थितियों और उससे अर्जित समाजवादी उपलब्धियों की ओर ज़माना होगा, जहां उनके गुरु नव्यवाची विषयों में उत्तरायण-पतन की समस्त गाथाएं अंतर्निहित हैं।

जिसके लिए उत्तरायण को वर्ष 1950, 1960, 1970 और 1980 के दशक की सियासी परिस्थितियों और उससे अर्जित समाजवादी उपलब्धियों की ओर ज़माना होगा, जहां उनके गुरु नव्यवाची विषयों में उत्तरायण-पतन की समस्त गाथाएं अंतर्निहित हैं।

जिसके लिए उत्तरायण को वर्ष 1950, 1960, 1970 और 1980 के दशक की सियासी परिस्थितियों और उससे अर्जित समाजवादी उपलब्धियों की ओर ज़माना होगा, जहां उनके गुरु नव्यवाची विषयों में उत्तरायण-पतन की समस्त गाथाएं अंतर्निहित हैं।

जिसक



## ओमिक्रॉन संक्रमण ने वैज्ञानिकों को उलझाया

कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर वैज्ञानिक अभी भी उलझन में हैं, ब्योकॉम्प्यूटर इसकी भयावहत को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में जहाँ इसका प्रौद्योग सबसे ज्यादा रहा है, वहाँ किए गए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि इसके संक्रमण के मामले हल्के हैं तथा पूर्व के संक्रमणों की तुलना में अस्पताल में भर्ती किए जाने की जरूरत कम पड़ रही है। नेवर में प्रकाशित रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि ओमिक्रोन संक्रमण में पूर्व की तुलना में अस्पताल में भर्ती किए जाने की दर 29 फीसदी कम है। बहु दावा एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी गती एजेंसी के आकड़ों को आवाहन बनाकर किया गया है। लेकिन इसी रिपोर्ट में डेनमार्क के आकड़ों का जिक्र किया गया है, जिसमें दावा है कि ओमिक्रोन एवं डेल्टा पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती होने की दर में अतर नहीं दिखता है। ब्रिटेन में भी ओमिक्रोन के मामले बढ़ते हैं तथा पूर्व की तुलना में अभी भी ज्यादा पाया जाता है। लेकिन इस वीच इंडियन टाइगर का लेज लंदन ने कहा कि ओमिक्रोन संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की दर डेल्टा की तुलना में कम नहीं प्रतीत होती है। एपेंडिनर्म यूनिवर्सिटी के एपिमोलाजिस्ट मार्क वुलहाड़स ने कहा कि अभी यह आकड़े बेहद सीमित दावर हैं। इसलिए किसी अतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है तथा इसके आधार पर कोई नीतिगत नियन्त्रण नहीं लिया जा सकता है। नई दिल्ली रिसर्च वर्कशॉप ने निवेशक प्रोफेसर जगत विश्वार कहते हैं कि अस्पताल में किनने ओमिक्रोन पीड़ित भर्ती हुए या नहीं इससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। ब्योकॉम्प्यूटर किसी देश में मध्यम लक्षणों वाले का अस्पताल में भर्ती करने की नीति है तो कहीं सिर्फ गंभीर मरीजों को ही भर्ती किया जाता है। यह उस देश की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है।

### डेढ़ से दो दिन में केस दोगुने हो रहे

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना का नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर बड़ी जानकारी दी। संगठन का कहना है कि डेढ़ से दो दिन में ओमिक्रोन के मामले दोगुने हो रहे हैं। जो चिंताजनक है। हालांकि, डब्ल्यूएचओ ने एक बार फैर कहा कि अभी भी इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि कोरोना वैक्सीन ओमिक्रोन के खिलाफ निकलती है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ओमिक्रोन उन देशों में डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले अधिक तेजी से फैल रहा है। जहाँ कम्यूनिटी ट्रांसमिशन दर्ज किया जा रुका है। वहाँ भी यह तेजी से बढ़ा है। जहाँ बड़ी संख्या में लोग इम्यूनिटी हासिल कर चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जहाँ बड़ी आबादी की टीका लग चुका है। भारत भी उन देशों में शामिल है।



## क्या होता है आंखों का लकवा

कई बार सेहत के प्रति लापरवाही बरतने या फिर जागरूकता की कमी की जगह से व्यक्ति को गंभीर रोगों का लकवा होना चाहता है। ऐसा ही एक रोग है आंखों की पुरुलियों का लकवा। ऑक्युलर पैरेलिसिस आंखों से जुड़ी ऐसी गंभीर बीमारी है, जिसमें आंखों को एक रोग बनाने के नियंत्रण पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। आइर जाने हैं आरिकर बरया है यह रोग, इसके लक्षण और बचाव के तरीके।

### क्या होता है आंखों का लकवा?

ऑक्युलर पैरेलिसिस को हिंदी भाषा में व्यक्ति अपनी आंखों का लकवा कहते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है, जिसमें आंखों की पुरुलियों का लकवा—हिलना बंद हो जाता है। जिसकी जगह से व्यक्ति को देखने में परेशानी होने लगती है। दरअसल हर व्यक्ति की आंखों में 6 एवं रेट्रोऑक्युलर मसल्स होते हैं। जिसमें से 4 रेट्राइ और 2 ऑब्स्ट्रॉल मसल्स होते हैं।

एक ऑक्युलर मसल्स की दस्ती से व्यक्ति अपनी आंखों को दाएं-बाएं, ऊपर-नीचे नापा लाता है। यदि किसी कारण इस एक्स्ट्रोऑक्युलर मसल्स में आंशिक रूप से लकवा हो जाए तो फिर आइबॉल का मूवमेंट प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति वाहने हुए भी अपनी आइबॉल की गति में नहीं लापाता है। इसी स्थिति को आंखों का लकवा कहा जाता है।

### आंखों के लकवा के लक्षण

- आंखों में तेज दर्द के साथ आंखें लाल होना और आंखों से लगातार पानी बहते रहना।
- आंखों की पुरुलियों का अचानक से एक ही दिशा में बने रहना या पलकें नीचे गिर जाना।
- डबल विजन जिसमें व्यक्ति को एक वस्तु दो दिखाई देती है।
- मरीज का जी मिलाना और चक्कर आना।



क्या आप 'इसोमनिया' के साथ-साथ 'ऑब्स्ट्रिविट्व स्लीप एपनिया' से भी जूँझ रहे हैं?

अगर हो तो संभल जाइ।

'यूरोपियन रेपिएटी जर्नल'

में छपे एक ऑस्ट्रेलियाई

अध्ययन ने 'इसोमनिया' और 'ऑब्स्ट्रिविट्व स्लीप एपनिया'

के कॉकटेल यानी 'कॉर्सिम्या'

को ज्यादा धातक कराया दिया

गया है। शोधकर्ताओं ने इसका

सामाना करने वाले लोगों में

हृदयरोगों से गौत का खत्या

कई गुना ज्यादा पाया है।

सबसे आम बीमारियां

विशेषज्ञों के मुताबिक 'इसोमनिया'

और 'ऑब्स्ट्रिविट्व स्लीप एपनिया'

ने बताया कि 'इसोमनिया' में व्यक्ति

को सोने में दिक्कत, बार-बार नीद

टूटने और जल आंख खुलने की

शिकायत सतती है। वहाँ,

'ऑब्स्ट्रिविट्व स्लीप एपनिया'

में खराटे, गला चोक होने और सांस लेने

में तकलीफ की समस्या आम है।

हाइपरट्रेशन

का जोखिम

डॉ. वैस्टर्यन लेवत के नेतृत्व में

शोधकर्ताओं ने नीद की बीमारियों से

जूँझ रहे 5000 से अधिक मरीजों के

## इंसोमनिया और ऑब्स्ट्रिविट्व स्लीप एपनिया का कॉकटेल है कॉर्सिम्या

ऐसे पीड़ित भी मौजूद हैं, जिन्हें दोनों की शिकायत होती है।

### क्या हैं प्रमुख लक्षण

पिलंडर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं

ने बताया कि 'इंसोमनिया'

में व्यक्ति

को सोने में दिक्कत, बार-

बार नीद

टूटने और जल आंख खुलने की

शिकायत सतती है।

वहाँ,

'ऑब्स्ट्रिविट्व स्लीप एपनिया'

में खराटे, गला चोक होने और सांस लेने

में तकलीफ की समस्या आम है।

असामिक मौत

का खतरा

कॉर्सिम्या

से पीड़ित लोगों के वक्त

से पहले मौत का शिकायत होते का

जोखिम भी 47 फीसदी अधिक दर्ज

किया गया है। वृक्षि,

'इंसोमनिया'

और 'ऑब्स्ट्रिविट्व स्लीप एपनिया'

का कॉकटेल ज्यादा ज्यान लेता है।

ज्यान लेता है। इन दोनों जीवों

को साथ में खाने से भरपूर पोषण मिलता है।

तो आइए जानते हैं दही और किशमिश का साथ में खाने के कायदे।

इम्युनिटी

दोनों को मिक्स कर खाने से इम्युनिटी

मजबूत होती है। इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट

रहता है। जिससे संक्रमण की चम्पाना कर रहे

मरीज में दूरपे के लक्षणों पर भी गौर

फरमाना जरूरी है।

इसलिए ठंडे के मौसम में जल्दी नहीं आते और जल्दी ठीक हो जाते हैं।

पान किया को करें दुरस्त

ठंड में आपकी निखारने के लिए घेरे

पर कुछ लगता है। लेकिन निखार नहीं

आता है तो दही और किशमिश का साथ में खाने के कायदे।





# जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनेंगे यूपी के युवा : योगी

गोरखपुर, 30 दिसम्बर (एजेन्सी)। मुख्यमंत्री योगी ने नववर्ष के दो दिन पूर्व जनपद को अईटीआई, पॉलिटेक्निक, गुरु गोरखनाथ शोधपीठ, राजकीय इटर कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अक्षयपात्रा केंट्रीयकृत एमडीएम रसोईघर, गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रावास, ड्रग वेरहाउस, ओवरब्रिज, फोरलेन, कई सड़कों-नालियों समेत हर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का उपहार दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्य अवश्वत जारी रहेगा।

लोकार्पण व शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईस्वी सन 2022 के आगमन के पहले गोरखपुर को कल और आज मिलाकर करीब 1850 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उपहार मिला है। इनमें मुख्यमंत्री योगी ने एक बड़े टेबलेट और स्मार्ट फोन में ऑनलाइन एजुकेशन के साथ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में तो मदर मिलेगी ही, इसमें स्टर्टअप, मुद्रा, स्टैंडअप आदि ऐसी प्रमुख योजनाओं की सविस्तार जानकारी होगी। यह युवाओं को नौकरी तलाशने वाला की बजाय नौकरी देने वाला बनाएंगी। स्टर्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने एक स्पेशल फंड भी बनाया है।

सीएम योगी गुरुवार को गोरखपुर को विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात देने के साथ ही 1305 करोड़ रुपये की लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास एं युवाओं में टेबलेट-स्मार्ट फोन वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। महंत दिव्यजयनाथ स्मृति पार्क में

सीएम योगी गुरुवार को परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही 1305 करोड़ रुपये की लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास एं युवाओं में टेबलेट-स्मार्ट फोन वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। महंत दिव्यजयनाथ स्मृति पार्क में

उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उन्होंने अगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि स्थानक, परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास एं युवाओं में टेबलेट-स्मार्ट फोन वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। महंत दिव्यजयनाथ स्मृति पार्क में

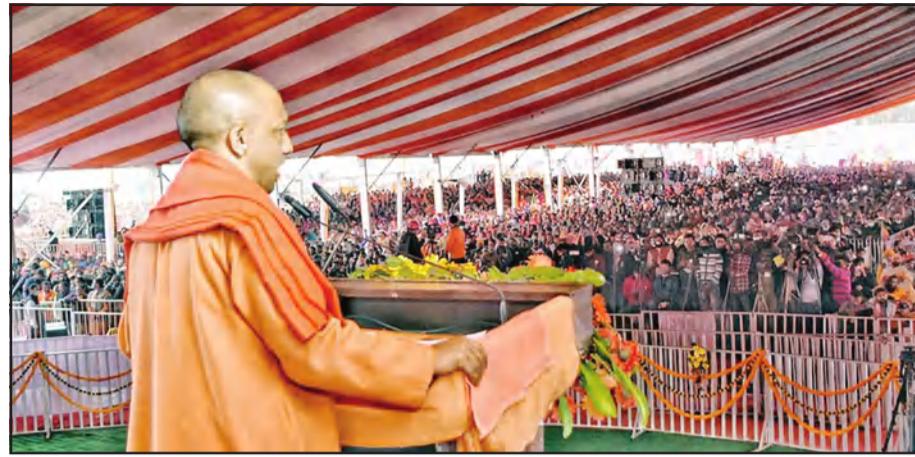
युवाओं को उपहार मिला है। लखनऊ में 60000 युवाओं

लोकार्पण व 285 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उपहार मिला है।

इनमें सबसे खास है वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शिलान्यास किया। समारोह में मुख्यमंत्री की जूँड़ीयां में एक हजार माध्यम से युवा वाटर स्पोर्ट्स के विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन व टेबलेट के वितरण किया गया। 24 युवाओं को मुख्यमंत्री की मंच पर अपने हाथों से टेबलेट व स्मार्ट फोन प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने इन विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद कर उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उन्होंने अगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

सीएम योगी ने कहा कि जगत का एक बार फिर दोहरा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता। विकास का एक बार को कराकर होता है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर और प्रदेश के बारे में नकारात्मक धारणा बदलने में कामयाबी प्रधानमंत्री ने दोदी के 'सबका साथ-सबका विकास' मंत्र से मिली। आज पूरे प्रदेश में इसका प्रभाव दिख रहा है।

लखनऊ से इसका शुभारंभ किया गया है। लखनऊ के बड़े कार्रवाई अवसर दिया है। राज्य में 4:30



लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, 1.61 करोड़ को अन्य रोजगार तथा 60 लाख स्वतः रोजगार से जोड़ गया। गरीबों के लिए मुफ्त मकान, मुफ्त शौचालय, मुफ्त विजली, मुफ्त राशन की व्यवस्था है, इस्वी सन 2022 के आगमन के पूर्व विकास का भव्य वातावरण बना है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को इस्वी सन 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए सबके मंगलमय जीवन की कामना भी की।

विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। गोरखपुर में रोशनी से जगमगाती चौड़ी सड़कें हैं तो सबको अनवरत बिजली मिल रही है।

सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के खतरे के लिए लोगों

लोकार्पण वितरण किया गया। 2017 के पहले तक हर दूसरे -तीसरे दिन प्रदेश में दंगा होता था। बाहर का कोई व्यक्ति यहां आकर निवेश नहीं करता चाहता था। 2017 के बाद बदलते यूपी को सब ने देखा है। यहां अपराध व भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाइ गई।

विकास पर फोकस किया गया। इसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है।

उन्होंने कहा कि इस सरकार ने नौकरी में योग्यता के आधार पर उद्घाटन हुआ जहां से महानगर के उद्घाटन हुआ जहां से बहाना भेदभाव विकास की व्यवस्था की है। कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी जा रही है और इस प्रदेश में सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए।

सुशील चंद्रा की अगुवाई में आयोग के 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के तीन दिवसीय समीक्षा दौरी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा निवाचन प्रक्रिया से जुड़े अन्य पक्षकारों के साथ कई दौरों के लिए कोरोना के खतरे से बचने के लिए लोगों

में दंगा होता था। आयोग के अगुवाई में आयोगी ने यहां खाद कार्रवाना करना चाहता था। 2017 के बाद बदलते यूपी को सब ने देखा है। यहां अपराध व भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाइ गई।

विकास पर फोकस किया गया। इसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है।

उन्होंने कहा कि इस सरकार ने नौकरी में योग्यता के आधार पर पूरी परदर्शिता से बिना भेदभाव

अवसर दिया है। राज्य में 4:30

## यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान एक घंटे अधिक होंगे : चुनाव आयोग

लखनऊ, 30 दिसम्बर (एजेन्सी)। चुनाव आयोग ने कोरोना सकट के फिर से उभरने की वजह से उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में नव्हितर समय से एक घंटा अधिक मतदान कराने सहित अन्य अहम फैसले किए हैं।

उन्होंने बताया कि कोरोना प्रतिक्रिया के खतरे के ध्यान में खतरे हुए आयोग ने नियमित कराते हुए आयोगी चुनाव में विधायिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए विशेष नियम के अन्तर्गत चंद्रा ने राज्य में राजनीति तैयारियों की तीन दिन तक चली समीक्षा के बाद गुरुवार कोरोना संबद्धता समेलन में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे के ध्यान में खतरे हुए आयोग उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र, नियम, प्रॉलॉन्ग मुक्त और कोरोना सुरक्षित चंद्रा ने राज्य में चुनावी तैयारियों की तीन दिन तक चली समीक्षा के बाद गुरुवार कोरोना सुरक्षित चुनाव कराने के लिए प्रतिवेद्ध है। चंद्रा ने कहा कि आयोग का यह प्रयास है कि आगामी चुनाव में विधायिकों, नारियों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए विशेष नियम के अन्तर्गत चंद्रा ने कहा कि आयोग का यह प्रयास है कि आगामी चुनाव में सभी लोगों को इस्वी सन 2022 के आगमन के पूर्व विकास का भव्य वातावरण बना है।

सुशील चंद्रा की अगुवाई में आयोग के 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के तीन दिवसीय समीक्षा दौरी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा निवाचन प्रक्रिया से जुड़े अन्य पक्षकारों के लिए कोरोना के खतरे के लिए लोगों

में दंगा होता था। आयोग के अगुवाई में आयोगी ने यहां खाद कार्रवाना करना चाहता था। 2017 के बाद बदलते यूपी को सब ने देखा है। यहां अपराध व भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाइ गई।

विकास पर फोकस किया गया। इसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है।

उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे के ध्यान में खतरे हुए आयोग ने नियमित लिया है कि मतदान के लिए बड़े घंटे दिन तक चला जाएगा। साथ कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी जा रही है और इस प्रदेश में सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए।

चंद्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 14 मई को समाप्त हो रहा है।

राज्य में कुल 403 विधानसभा

निवाचन क्षेत्रों में 317 समाप्त्य, 84

अनुसूचित जातियों तथा 02

अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।

इन सभी सीटों पर विधानसभा

कोरोना के संबंध में खतरे हुए

सहित अवधिकारी ने यहां चुनाव के लिए लिए कोरोना के खतरे के लिए लोगों

में दंगा होता था। आयोग के अगुवाई में आयोगी ने यहां खाद कार्रवाना करना चाहता था। 2017 के बाद बदलते यूपी को सब ने देखा है। यहां अपराध व भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाइ गई।